Bhaskara-II will mark the close of the first phase of the experimental system and lead to the semi-operational system of generating and utilising satellite based remotely sensed data; one vital component in this phase will be the Indian Remote Sensing Satellite Project for which considerable user coordination and design activity has been done during the past three years and project activities are about to commence.

After Aryabhata and Bhaskara-I, Bhaskara-II marks another important milestone in the continuing Indo-Soviet cooperation in Space Research.

The entire nation is proud of the contributions and achievements of our scientists, technologists, engineers and the workers who have made this project a success and I hope this august House will join me in congratulating them.

12.14 hrs.

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS GENERAL), 1981-82

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI MAGANBHAI BAROT): On behalf of Shri R. Venkataraman, I beg to present a statement (Hindi and English versions) showing Supplementary Demands for Grants in respect of the Budget (General) for 1981-82.

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (GENERAL), 1979-80

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI MAGANBHAI BAROT): On behalf of Shri R. Venkataraman, I beg to present a statement (Hindi and English versions) showing Demands for Excess Grants in respect of the Budget (General) for 1979-80.

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (ASSAM), 1981-82

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI MAGANBHAI BAROT): On behalf of Shri R. Venkataraman, I beg to present a statement (Hindi and English versions) showing Supplementary Demands for Grants in respect of the State of Assam for 1981-82.

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS), 1981-82

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI KEDAR PANDEY): Sir, I beg to present a statement (Hindi and English versions) showing Supplementary Demands for Grants in respect of the Budget (Railways) for 1981-82.

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (RAILWAYS), 1979-80

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI KEDAR PANDEY): Sir, I beg to present a statement (Hindi and English versions) showing Demands for Excess Grants in respect of the Budget (Railways) for 1979-80.

---

12 17 hrs

MATTERS UNDER RULE 377

(i) Industrialisation in the Intetior of Himachal Pradesh

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : देश में औद्योगीकरण का भारी तादाद में विस्तार किया जा रहा है । हिमाचल प्रदेश के सम्बन्ध में उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हिमाचल में कई करोड़ के उद्योगों की स्थापना पोंटा साहब, परवानू, बर्राटीवाला, नालागढ़, महतपुर, इन्दौरा इत्यादि स्थानों पर की जा रही है । कई उद्योग इस प्रकार

[श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी]

के हैं जो अब उत्पादन कर रहे हैं। परन्तु अब अधिक उद्योगों का फैलाव करने से सीमा क्षेत्र जो कि हिमाचल प्रदेश का है, उसी का विकास हो रहा है और जो वहां पर मैदानी क्षेत्र की भूमि है वह काफी उपजाऊ है और उसका अधिग्रहण किया जा रहा है जिससे वहां के लोगों में परेशानी उत्पन्न हो रही है और दूसरी ओर जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उन में यह भावना पैदा होती जा रही है कि उद्योगों की स्थापना हिमाचल के भीतरी भाग में होनी चाहिए ताकि हिमाचल की समस्त जनता इससे लाभान्वित हो सके और जो वहां के युवक और युवतियां हैं, इस वक्त बेरोजगारी की जटिल समस्या में फंसे हुए हैं, उनको रोजगार प्राप्त हो सके। इस वक्त देखने में ऐसा आ रहा है कि जो जो उद्योग सीमा क्षेत्र में स्थापित किए जा रहे हैं उन में उस क्षेत्र के लोगों को पूर्ण रूप से रोजगार प्राप्त नहीं है। मैं यह भी अनुरोध करूंगा कि राज्य सरकार को इस मामले में मार्ग निर्देश जारी किए जाएं कि हिमाचल के लोगों के उत्थान के लिए जिला सिरमौर; शिमला, सोलन के उन क्षेत्रों में उद्योग बस्तियां कायम करें जहां भूमि उजाड़ पड़ी है, न कि उपजाऊ भूमि में। मुझे नालागढ़ क्षेत्र के बहुत से गांव के लोगों की तरफ से मांग आई है कि उन की जमीन पर क्रय विक्रय की पाबन्दी लगाई जा रही है और उन्हें वहां से बेदखल होना पड़ेगा। उनकी भूमि सुरक्षित रखी जाए और बेदखल होने से बचाया जाए।

12 19 hrs

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

अतः मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे सीमा क्षेत्र में पंजाब का क्षेत्र पड़ता है जिसमें कई किस्म की समस्याएं हैं और पहाड़ी क्षेत्र के लोग अपने पसन्द होते हैं उनके लिए कानूनी तौर पर अमन-आभा कायम करने के लिए कठिनाइयां पैदा हो जायेंगी।

अतः मंत्री महोदय, हिमाचल के भीतरी भाग में उद्योग लगाने हेतु फौरन ध्यान दें। जब उद्योगों की स्थापना हो जाए तो इन दूरदराज के इलाको में स्थापित हुए उद्योगों की पैदावार को बाजार में पहुंचाने हेतु परिवहन सुविधाएं और माल के ढुलान पर, जो बाजार तक पहुंचाना आवश्यक होगा, सब्सिडी अनुदान के रूप में देने की कृपा करें।

(ii) CLEARANCE OF PILED UP STOCKS OF IRON ORE AT THE PIT AND RAILHEADS IN BANSPANI-BARHIL SECTOR IN ORISSA.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Chintamani Jena. Not present. Shri Lakshman Mallick.

SHRI LAKSHMAN MALLICK (Jagatsinghpur): Production of minerals in Orissa suffered a great setback owing to the piling up of 1.5 million tonnes of iron-ore valued at Rs. 6 crores at different pit and railheads. During last two months, 15 iron-ore and two chromite ore mines have been closed down in the Barbil Banspani sector. This has resulted in the retrenchment of 15,000 workers, most of them are Adivasis and Harijans.

According to the latest assessment, over 6 million tonnes of iron-ore worth Rs. 100/- crores has stockpiled at steel plants in the country. On the other hand, the export of iron-ore has declined sharply. These two main factors led the mining activities to a standstill position in Orissa. The State's export of ron-ore had slumped from 3 million tonnes during 1975-76 to 1.96 million tonnes during 1980-81. The situation has worsened in the